वाहनों पर रोड टैक्स में 50% छूट को मंजूरी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक

प्रभारी मंत्री सिलावट ने कहा- इस फैसले से मेले में व्यापार बढ़ेगा

ग्वालियर, 13 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में ग्वालियर व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट की मंजूरी दी गई.

इस निर्णय पर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल में मुख्यमंत्री से भेंट कर ग्वालियरवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया. प्रभारी मंत्री सिलावट ने कहा कि इस फैसले से ग्वालियर मेले में व्यापार बढ़ेगा और ग्वालियर-चंबल अंचल सहित पूरे मध्यप्रदेश के निवासियों और उद्योग जगत को फायदा होगा. मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया, सचिव महेश मुदगल, संयुक्त अध्यक्ष एवं प्रवक्ता अनिल पुनियानी समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री सिलावट और ऊर्जा मंत्री तोमर का धन्यवाद दिया. विगत दिनों मेला व्यापारी संघ ने ज्ञापन देकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोड टैक्स छूट की विलंबित घोषणा पर चिंता जताई थी.

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इसे गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट में मंजूरी दिलाई. मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से मेला की रौनक बढ़ेगी और टैक्स छूट का इंतजार कर रहे खरीदार रियायती दामों पर वाहन खरीद सकेंगे. इससे मेला में बिक्री बढ़ने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियाँ भी सक्रिय होंगी और ग्वालियर मेला और अधिक आकर्षक बनेगा.

भारत सिंह ने टैक्स में छूट पर आभार जताया

ग्वालियर व्यापार मेला में वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलने पर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भोपाल में भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस छूट से पूरे ग्वालियर अंचल की जनता को लाभ मिलेगा और क्षेत्र में विकास एवं व्यापार को नई गति मिलेगी. सांसद ने बताया कि उन्होंने मेला में रोड टैक्स में छूट देने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध किया था. उनके अनुसार, ग्वालियर व्यापार मेला मध्यभारत क्षेत्र का एकमात्र मेला है, जिसमें पिछले वर्षों में भी वाहनों की खरीद पर छूट दी जाती रही है. इस छूट से मेला में वाहन बिक्री और कारोबार में वृद्धि होगी और मेला की रौनक बढ़ेगी. सांसद ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई कि इस प्रथा को आगामी वर्षों में भी जारी रखा जाएगा.

तीस लाख किसानों को सोलर पंप मिलेंगे

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि इस वर्ष डिण्डोरी जिले में मध्यप्रदेश राज्य श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी. ग्वालियर में सरसों अनुसंधान और उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जायेगा. डॉ यादव ने कैबिनेट से पहले अपने संबोधन में कहा कि 30 लाख से अधिक किसानों को अगले तीन साल में सोलर पावर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रदेश का सिंचाई रकबा अभी 65 लाख हेक्टेयर है, इसे बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है. कृषक कल्याण वर्ष का कैलेंडर जारी किया गया है. वर्ष भर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन व कुछ अन्य विभाग मिलकर कार्य करेंगे.

15 जनवरी के बाद फिर बढ़ सकती है ठंड

मौसम में थोड़ी नरमी, सर्दी में मिली राहत

18 जनवरी के आसपास तापमान में गिरावट होने की संभावना

भोपाल, 13 जनवरी . पिछले एक सप्ताह की कड़ाके की सर्दी के बाद मौसम में थोड़ी नरमी देखने को मिली है, लेकिन रात में ठंडक अभी भी बनी हुई है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दो दिन मौसम इसी तरह सामान्य रहने की संभावना है. हालांकि, 15 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में बर्फबारी, कोहरा और बारिश की संभावना है, जिससे प्रदेश में हल्के बादल छा सकते हैं और नमी बढ़ सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, 17-18 जनवरी के आसपास तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे सर्दी फिर बढ़ सकती है. इस समय प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है. पिछले तीन-चार दिनों से तापमान में स्थिरता देखी गई है.

बीते दिन अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान में रविवार की तुलना में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अधिकतम तापमान यथावत रहा. पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी भी जिले में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और सभी जिले सामान्य रहे. पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 किलोमीटर की ऊँचाई पर सक्रिय है.

कांग्रेस ने दी कानूनी कदम की चेतावनी

आरोप : फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों पर कार्रवाई

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मंगलवार को राज्य सरकार पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों के मामलों में प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अहिरवार ने कहा कि कई फर्जी जाति प्रमाणपत्र ताकतवर लोगों द्वारा बनवाए गए, जिनमें कुछ आईएएस अधिकारियों की कथित संलिप्तता भी सामने आई.

उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक मामलों में जांच होने के बावजूद दोषियों को 'क्लीन चिट' दे दी गई, जिससे जांच की निष्पक्षता और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

अहिरवार ने आगे कहा कि प्रदेश में फर्जी एससी प्रमाणपत्रों से जुड़े 223 से अधिक मामले लंबित हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

लगातार हो रही देरी पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रभावित समाज और कांग्रेस पार्टी के पास न्यायिक हस्तक्षेप का रास्ता ही बचा है. उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर फर्जी एससी प्रमाणपत्र धारकों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

मंत्री प्रहलाद पटेल ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचें. इस दौरान उनके साथ विभाग की राज्य मंत्री राधा सिंह भी थीं.

मंत्री और राज्य मंत्री ने पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की शिकायतें और समस्याएं सुनीं और उनका समाधान किया. भाजपा प्रदेश संगठन ने नई व्यवस्था तय की है, जिसके तहत मंत्री रोटेशन के आधार पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और यहां कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनते हैं. पटेल ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन समस्याओं के निराकरण के लिए महीने के दूसरे मंगलवार का दिन मेरे लिए नियत है.

निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज मैंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से मुलाकात की. इस दौरान कुल 69 लोगों ने मुझसे संपर्क कर अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा किए. अधिकांश समस्याएं मेरे विभाग से संबंधित थीं, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए. कुछ समस्याएं अन्य विभागों से संबंधित थीं, जिन्हें संबंधित विभागीय मंत्रियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई.

सीएमएचओ के खिलाफ खोला मोर्चा

एनएसयूआई ने दी आंदोलन की चेतावनी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बदहाल होती जा रही हैं.

निजी और शासकीय दोनों ही स्वास्थ्य संस्थानों में अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं. एक ओर निजी अस्पतालों पर नियमों की अनदेखी के आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है. इन सबके बीच सबसे गंभीर सवाल सीएमएचओ कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे हैं. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मंगलवार को भोपाल के सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा द्वारा जारी एक आदेश का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वर्षों से नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य कर्मचारियों से बाबूगिरी और संवेदनशील प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं.

परमार ने कहा कि फार्मासिस्ट और नेत्र सहायक जैसे तकनीकी कर्मचारियों को नर्सिंग होम और पीसीपीएनडीटी जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं का प्रभारी बना दिया गया है, जबकि उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है. एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने आरोप लगाया कि ऐसे 'गलत प्रयोग' स्वास्थ्य सेवाओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन पर तुरंत रोक नहीं लगी और जिम्मेदारी तय नहीं हुई, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा.

जमीनी विवाद में गोलीबारी

02 लोग गंभीर रूप से घायल

भिंड, 13 जनवरी. जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हुआ. विवाद की शुरुआत खेत में खाद डालने को लेकर हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस और मारपीट हुई. इस दौरान एक युवक बंदूक लेकर मौके पर पहुंचा और दो राउंड फायर किए.

घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल दो लोगों कल्ली पुत्र केशव सिंह गुर्जर और सत्यभान सिंह गुर्जर को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. वहीं, अन्य घायलों को गोहद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद जमीन के अधिकार और खेती को लेकर हुआ था. घटना के बाद इलाके में तनाव देखा गया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

हाईकोर्ट ने हत्या की सजा बरकरार रखी

पत्नी की हत्या का मामला

7 चोटों से स्पष्ट हुआ हत्या का इरादा

जबलपुर, 13 जनवरी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतिका के शरीर पर सात चोटों के निशान पाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपी ने हत्या के इरादे से हमला किया था.

हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की युगलपीठ ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया. उमरिया निवासी शंकर बैगा ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील में कहा गया कि बैगा समुदाय का सदस्य होने के कारण और शराब पीने की स्थिति में उसने पत्नी सुखबंती के साथ 14 जनवरी 2019 को शराब का सेवन किया. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने डंडे से पत्नी पर हमला किया. पत्नी दो दिन बाद, 16 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई. घटना के बाद पाली पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की. अपील में आरोपित ने तर्क दिया कि वह घटना के समय नशे में था और हत्या के नतीजे को समझने की स्थिति में नहीं था. उसने हत्या का इरादा नहीं किया था. उसने सिर्फ डंडे से मारपीट की थी और कोई घातक हथियार प्रयोग नहीं किया.

युगलपीठ ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार अपीलकर्ता अपनी पत्नी पर हमला कर रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाली महिला बीच-बचाव के लिए आई थी, जिस पर आरोपी ने मारने की धमकी दी और थप्पड़ मारा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि मृतिका नशे में नहीं थी. रिपोर्ट में सात चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या का इरादा सिद्ध होता है. इसी आधार पर कोर्ट ने अपील खारिज कर दी.

अनारक्षित टिकट पर 3% डिजिटल लाभ

14 जनवरी से 14 जुलाई तक सुविधा उपलब्ध होगी

भोपाल, 13 जनवरी . भारतीय रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और यात्रियों को सीधे आर्थिक लाभ देने के लिए रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट पर 3 प्रतिशत बोनस छूट की सुविधा लागू करने की घोषणा की है.

यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक आधार पर उपलब्ध होगी. पहले यह लाभ केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर ही मिलता था, लेकिन अब सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि पर भी मिलेगा. इससे यात्रियों को अनारक्षित टिकट बुकिंग में प्रत्यक्ष बचत होगी. यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी देने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. यह पहल कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित करने के साथ डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती प्रदान करेगी.

102 करोड़ का ऑरिजिनेटिंग राजस्व किया अर्जित

भोपाल .महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में दिसम्बर माह में पूरे पश्चिम मध्य रेल ने 572 करोड़ 57 लाख रुपए का माल यातायात से ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के 489 करोड़ 01 लाख रुपए की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है. रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य 532 करोड़ 05 लाख रुपए से यह लगभग 8 प्रतिशत अधिक है. भोपाल मंडल ने इसी दौरान 102 करोड़ 05 लाख रुपए का ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया. माल यातायात बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाकर खंड की क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार किया गया है. गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और साइडिंग का विस्तार, मालगाड़ियों के डिटेंशन में कमी, टर्मिनल वर्किंग में सुधार और माल गोदामों में चौबीस घंटे लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा लागू की गई है.

विशेष रूप से दैनिक यात्री और उपनगरीय क्षेत्र के लोग इस सुविधा से लाभान्वित होंगे. सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के उपयोगकर्ता अपनी पहचान से लॉग इन कर सकते हैं. ऐप पर अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन-स्टेशन जानकारी और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

समय में काम नहीं, तो कार्रवाई होगी

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी वर्किंग एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं.

उन्होंने कहा कि यदि कोई एजेंसी तय टाइमलाइन में कार्य पूर्ण नहीं करती है, तो उसके विरुद्ध निर्माण अनुबंध की शर्तों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मप्र पुलिस हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पीआईयू, आईडीए, बीडीए, यूडीए और भवन विकास निगम सहित विभिन्न वर्किंग एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि मासिक आधार पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा स्टेप-बाय-स्टेप और मंथ-बाय-मंथ लक्ष्य तय कर निर्माण कार्य पूरे किए जाएं. मंत्री ने कहा कि प्रत्येक एजेंसी अपनी कार्ययोजना स्पष्ट रूप से विभाग को उपलब्ध कराए.

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए मंत्री सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग में एक तकनीकी विंग गठित करने के निर्देश दिए. यह तकनीकी विंग विभागीय जांच दल के रूप में कार्य करेगा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं मानकों की नियमित जांच करेगा. उन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस का मजबूत सिस्टम विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.

मध्यप्रदेश में अशासकीय स्कूलों की मान्यता-नवीनीकरण की तिथि बढ़ी

भोपाल. मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित अशासकीय स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की तिथि को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण अथवा नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा. पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी लेकिन तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं के मद्देनजर इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी किया गया है.

बैठक कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी

40 किमी सीवर लाइन की टेस्टिंग का काम पूरा

शिवपुरी, 13 जनवरी. शहर में करीब 14 साल पहले 2011 में सीवर लाइन का काम शुरू हुआ था. प्रोजेक्ट को तीन साल में पूरा होना था, परंतु 14 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है. इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी चिंतित हैं.

इसी के चलते कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों से एक-एक बिंदु पर चर्चा की. उनका कहना था कि अब यह पूरा मामला मेरे हार्ड ड्राइव में चला गया. अब मैं और मेरा हार्ड ड्राइव पूरी तरह इस प्रोजेक्ट पर लग गए हैं. अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाना मेरी प्राथमिकता है. उनका कहना था कि अब तक शिवपुरी शहर की 40 किमी सीवर लाइन की टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है. 55 किमी सीवर लाइन की टेस्टिंग और क्लीनिंग का काम बाकी है. इसके अलावा सीवर लाइन में एचटीपी डिस्फ्यूजर लगाने की जरूरत है और लाइन में 34 चेम्बर डेमेज हैं, जिन्हें ठीक करवाना है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीवर लाइन का 60 करोड़ रुपये का फेज टू कम्पलीट पड़ा है, परंतु मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जब तक फेज वन कम्पलीट नहीं हो जाता. आमजन संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक फेज टू का काम शुरू नहीं करने दूंगा. उन्होंने सीवेज का पानी जलाशयों पर जाने पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए उसे रोकने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ लोहड़ी पर्व मनाया...

इंदौर. सिंधी समाज ने हर्षोल्लास व परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ लोहड़ी पर्व मनाया. अग्नि प्रज्वलन कर समाजजनों ने सुख-समृद्धि की कामना की.